नईदुनिया

संपादकीय

हत्यारा बना मास्टर और सिस्टम सोता रहा चालीस साल तक

तेलंगाना *हाई कोर्ट में सामने आया एक मामला पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा करता है। हत्या के दोषी एक व्यक्ति को 30 दिन की पैरोल मिली थी। वह 17 दिसंबर 1983 को पैरोल पर बाहर आया और फिर कभी जेल नहीं लौटा। सजा पाए व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था, लेकिन वह सरकारी स्कूल में नौकरी करता रहा और 2013 में रिटायर भी हो गया। 2024 तक वह खुलेआम घूमता रहा और उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड तक मिल गया। किसी को भनक नहीं लगी। सवाल है कि यह किसकी नाकामी है - जेल प्रशासन की, पुलिस की या उस पूरी व्यवस्था की, जो अपराधियों को पकड़कर जेल में रखने का दावा करती है?*

सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। 17 दिसंबर 1983 को आरोपी को 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। नियम के मुताबिक उसे 17 मार्च 1984 तक जेल लौटना था, लेकिन वह नहीं आया। जेल प्रशासन ने कागजों में उसे फरार दिखाया और मामला आगे बढ़ाने के बजाय फाइल बंद कर दी। पुलिस ने भी एक-दो बार खानापूर्ति के लिए पत्र भेजे और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरी ओर वह व्यक्ति बाहर अपना नया जीवन शुरू कर चुका था। उसने सरकारी नौकरी हासिल की, बच्चों को पढ़ाया और वर्षों तक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीता रहा। जिस व्यक्ति पर हत्या का दोष सिद्ध हो चुका था, वही बच्चों को ईमानदारी और कानून का पाठ पढ़ाता रहा।

जरा उस पीड़ित परिवार के बारे में सोचिए, जिसने अपना कोई खोया था। आरोपी को सजा मिलने के बाद परिवार को लगा होगा कि न्याय हुआ, लेकिन कातिल तो 30 दिन की पैरोल के बाद ही आजाद हो गया और सरकारी शिक्षक बन बैठा। परिवार चार दशक तक इस उम्मीद में रहा होगा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून की निगरानी करने वाला तंत्र ही सोया रहा। यह केवल एक कैदी के फरार होने का मामला नहीं है। यह पीड़ित परिवार के साथ न्याय की दूसरी हत्या है।

सबसे बड़ा सवाल जेल प्रशासन पर है। पैरोल पर गया व्यक्ति तय समय पर वापस नहीं लौटा तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसकी तलाश के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या किया? क्या पैरोल की निगरानी के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी? यदि पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजे गए थे और बाद में स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई गई थी, तो कार्रवाई जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दी? सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे व्यक्ति को दशकों तक खोज न पाना पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इससे भी बड़ा सवाल सरकारी नौकरी मिलने का है। सरकारी सेवा में पुलिस सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र की प्रक्रिया होती है। फिर हत्या के दोषी और फरार व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं आया? यदि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी मिली तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और यदि सत्यापन के बावजूद नौकरी मिली तो व्यवस्था की गंभीर खामी सामने आती है। 2004 में उसे बेस्ट टीचर का सम्मान मिलना तो विडंबना की पराकाष्ठा है।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मामले पर चिंता जताते हुए पैरोल खत्म होने के बाद कैदियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों की जरूरत बताई है। सरकार को इसे महज एक मामले के रूप में नहीं देखना चाहिए। जेल और पुलिस के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ना होगा। पैरोल पर गए कैदियों की नियमित निगरानी, समय पर हाजिरी और तय अवधि में वापसी सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी नौकरी में सत्यापन व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाना होगा। कानून सबके लिए समान है, लेकिन उसकी निगरानी करने वाला सिस्टम यदि चालीस साल तक सोता रहे तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?

वाह रे हमारा सिस्टम, जिसने एक हत्यारे को चालीस साल तक मास्टर बनाए रखा और न्याय को जेल में बंद रखा।

आजकल

ट्रिपल आईटी में सीएसई का जलवा सिविल-इलेक्ट्रिकल से मोहभंग

मध्यप्रदेश के ट्रिपल आईटी सहित इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल जो तस्वीर उभरी है, वह साफ बताती है कि छात्रों का रुझान तेजी से बदल चुका है। सत्र 2025-26 के एडमिशन आंकड़े और सत्र 2026-27 के शुरुआती रुझान बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस से जुड़ी ब्रांचों में छात्रों की भीड़ बढ़ी है, जबकि सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसी पारंपरिक ब्रांचों में एडमिशन कम हुए हैं। यह बदलाव केवल पसंद का नहीं, बल्कि भविष्य की सोच का नतीजा है।

डीटीई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026-27 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) में 15,180 सीटों पर एडमिशन का रुझान है, जबकि पिछले वर्ष 2025-26 में यह संख्या 16,435 थी। इसी तरह सीएसई एआई एंड मशीन लर्निंग में 5,660 के मुकाबले 6,862 और सिविल इंजीनियरिंग में 2,961 के मुकाबले 3,070 का आंकड़ा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1,419 के मुकाबले 1,576 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 1,055 के मुकाबले 1,141 का रुझान दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कोर ब्रांच की तुलना में कंप्यूटर से जुड़ी शाखाओं की मांग अधिक है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपल आईटी) भोपाल में सत्र 2025-26 के एडमिशन के अनुसार 1,189 सीटों में से 1,068 सीटें भर गईं, जबकि 121 सीटें खाली हैं। कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच सबसे ज्यादा डिमांड में है। आंकड़ों के अनुसार एडमिशन का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले कंप्यूटर साइंस और एआई की ब्रांचों में गया है। कुल मिलाकर कंप्यूटर से जुड़ी ब्रांचों में छात्रों की होड़ है, जबकि सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसी परंपरागत शाखाएं पिछड़ रही हैं।

एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में रोजगार के बेहतर अवसर और अच्छे पैकेज छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। जेईई में भी बच्चों का झुकाव एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की ओर है। नौकरी बाजार में सॉफ्टवेयर, एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की मांग बढ़ रही है। वहीं कोर ब्रांच में सरकारी नौकरियों के अलावा निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पैकेज मिलने से छात्र उधर नहीं जा रहे हैं।

नई कूटनीति से बदल रहे वैश्विक समीकरण

चीन से रूस तक, अमेरिका से जापान तक हर तरफ दिख रहा है भारत का दम

वैश्विक मंच पर भारत की नई रणनीति से बदलती वैश्विक राजनीति के संकेत निकाले जा रहे हैं। मंथन 2026 में वैश्विक राजनीति में इन दिनों भारत सबसे अधिक चर्चा में है। वजह है भारत की नई कूटनीति और संतुलित विदेश नीति, जिसने दुनिया के बड़े-बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान और कनाडा जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों में जो नया मोड़ आया है, वह आने वाले समय में विश्व का नया परिदृश्य स्थापित करता नजर आ रहा है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा और उससे पहले अमेरिका के साथ चल रही टैरिफ वार्ता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है।

वर्ष 2021 के बाद किसी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक का यह पहला रूस दौरा है। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका-रूस के बीच तनाव कम करने के चैनल, वार्ताओं और तनाव घटाने के तहत इसे बेहद संवेदनशील कदम माना जा रहा है। रूस के दौरे को रोकने के लिए कहा था। रूस के साथ-साथ ईरान का मुद्दा भी इस दौरे को और अहम बनाता है, क्योंकि मॉस्को-तेहरान संबंध अमेरिका के लिए बड़ी चिंता हैं।

इसी दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25 अगस्त को बीजिंग में थे। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा विवाद पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता की। बातचीत में सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। डोभाल का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत-चीन संबंधों में हाल के सुधार के बीच हो रहा है। सितंबर में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क बढ़ा है। चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी डोभाल की मुलाकात हुई।

भारत के दो दिवसीय जापान दौरे में पीयूष गोयल, कनाडा में निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी अहम भूमिका में हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर हैं। वह करीब 200 सदस्यों वाले भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसे जापान के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के दौरे पर हैं। कनाडा में वह भारत-कनाडा के पहले इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग में हिस्सा लेंगी। यहां ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, तकनीक, निवेश और सप्लाई चेन जैसे मुद्दे अहम हैं।

भारत एक साथ इतने देशों से बातचीत का दायरा बढ़ा रहा है कि दुनिया हैरान है। एक तरफ अमेरिका से टैरिफ और व्यापार पर बात हो रही है तो दूसरी तरफ रूस से तेल और रक्षा सौदों पर चर्चा जारी है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश चल रही है तो जापान के साथ निवेश और तकनीक पर फोकस है। कनाडा के साथ संबंधों में जो खटास आई थी, उसे भी दूर करने की कोशिश हो रही है। यह भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है।

अमेरिका और रूस के बीच चल रहे तनाव की स्थिति में भारत ने खुद को एक पुल की तरह स्थापित किया है। अमेरिका भारत को क्वाड का अहम साझेदार मानता है तो रूस भारत को अपना सबसे पुराना मित्र मानता है। भारत ने यूक्रेन युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया और अपनी तटस्थता बनाए रखी। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता की बनी है। अब जब अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के चैनल खुल रहे हैं तो भारत की भूमिका और भी अहम हो गई है।

भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से तनाव रहा है, लेकिन अब दोनों देश संबंधों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डोभाल और वांग यी की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सीमा पर शांति जरूरी है। भारत चीन के साथ व्यापार तो जारी रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहता। यही कारण है कि भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है और साथ-साथ कूटनीतिक बातचीत भी जारी रखे हुए है।

जापान भारत का प्रमुख निवेशक है और भारत जापान के साथ सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा में बड़ा सहयोग चाहता है। वहीं कनाडा के साथ संबंधों में पिछले वर्ष जो गिरावट आई थी, उसे अब सुधारने की कोशिश हो रही है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। भारत की कोशिश है कि पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाए, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो।

पाकिस्तान की मरियम नवाज भी चीन में हैं। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ 25 अगस्त को चार दिन के आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचीं। दौरे की शुरुआत शिनजियांग के उरुमकी से हुई। पंजाब और चीन के बीच कृषि, तकनीक और निवेश सहयोग बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है।

कुल मिलाकर भारत की कूटनीति अब दुनिया में एक नए परिदृश्य की ओर इशारा कर रही है। भारत न तो अमेरिका का पिछलग्गू है और न ही रूस का विरोधी। वह अपने हितों के अनुसार हर देश से रिश्ते रख रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश भारत को अपने साथ रखना चाहता है। भारत की यह संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति ही उसे विश्व गुरु की ओर ले जा रही है। आने वाले समय में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और जी-20 की बैठकों में भारत की भूमिका और भी अहम होगी। यह तय है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

अब सेंध नहीं लगा पाएगा कोई दुश्मन, आसमान में तैनात रहेगा भारत का अभेद्य कवच

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, वाहक 6 को हेलीकॉप्टर जैसे मदरशिप प्लेटफॉर्म सबल 20 पर फिट किया गया है। इसमें अलख माइक्रो यूएवी शामिल हैं। इन छोटे ड्रोन का इस्तेमाल अलग-अलग भूमिकाओं के लिए किया जाता है। यह प्रणाली अलख माइक्रो यूएवी के दो प्रमुख वेरिएंट से लैस है। अलख एस को निगरानी और लक्ष्य की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अलख के को लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है।

भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगा दी है। ड्रोन आधारित सैन्य अभियानों की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भारत ने स्वदेशी वाहक 6 मल्टी-ड्रोन मदरशिप सिस्टम विकसित किया है। इस प्रणाली को निजी कंपनी एंड्योरएयर ने सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है। सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक मदरशिप से एक साथ कई माइक्रो ड्रोन हवा में तैनात किए जा सकें और उनके जरिए निगरानी से लेकर लक्ष्य की पहचान तथा कार्रवाई तक के काम पूरे किए जा सकें।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, वाहक 6 को हेलीकॉप्टर जैसे मदरशिप प्लेटफॉर्म सबल 20 पर फिट किया गया है। इसमें अलख माइक्रो यूएवी शामिल हैं। इन छोटे ड्रोन का इस्तेमाल अलग-अलग भूमिकाओं के लिए किया जाता है। यह प्रणाली अलख माइक्रो यूएवी के दो प्रमुख वेरिएंट से लैस है। अलख एस को निगरानी और लक्ष्य की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अलख के को लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है।

भारत की सीमाएं चाहे पाकिस्तान से लगी हों या चीन से, हर जगह दुर्गम इलाका है। पहाड़, जंगल और बर्फीले क्षेत्रों में हर जगह जवान तैनात करना मुश्किल होता है। ऐसे में वाहक 6 सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिस्टम उड़ान भरने के बाद लंबे समय तक हवा में रह सकता है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। यदि सीमा पर कोई हलचल होती है तो मदरशिप से निकले छोटे ड्रोन तुरंत उस इलाके में जाकर सटीक जानकारी भेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं।

भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा कंपनियों को देश के भीतर उत्पादन के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य मिसाइल प्रणालियों को अनुसंधान और विकास के चरण से औद्योगिक उत्पादन तक पहुंचाना है। इससे निजी कंपनियां भी मिसाइल बना सकेंगी। इससे देश में रक्षा उत्पादन बढ़ेगा और विदेशों पर निर्भरता कम होगी।

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में हुए युद्धों ने साबित किया है कि आने वाला समय ड्रोन युद्ध का है। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध तक ड्रोन ने निर्णायक भूमिका निभाई है। भारत ने इस बदलाव को समय रहते समझ लिया है। वाहक 6 जैसे सिस्टम से भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में कार्रवाई करने में भी सक्षम होगा।

इस सिस्टम के आने से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब भारत की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ की कोशिशों पर आसमान से निगरानी रखी जा सकेगी। दिन हो या रात, कोहरा हो या बर्फबारी, आधुनिक ड्रोन तकनीक निगरानी की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है।

इस स्वदेशी सिस्टम के निर्माण से देश में नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। एंड्योरएयर जैसी स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रक्षा तकनीक के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत को रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनाना है। वाहक 6 इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

वाहक 6 मल्टी-ड्रोन मदरशिप सिस्टम भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि बदलते युद्धक्षेत्र के अनुरूप बदलती रक्षा सोच का संकेत है। अब हवा में तैनात ड्रोन सीमाओं पर नजर रखेंगे और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाने में मदद करेंगे। यह उस भारत की तस्वीर है, जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

इन्फ्लुएंजा से डरो नहीं, लड़ो - सरकार बोली, नया खतरा नहीं

देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने के बाद लोगों में चर्चा तेज है कि कहीं फिर कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई। इसी बीच केंद्र सरकार और आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। देश में जो वायरस फैल रहा है, वह पुराना मौसमी वायरस ही है और उसका रूप भी सामान्य बदलाव वाला है।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि देशभर में निगरानी जारी है और अभी तक किसी नए या खतरनाक स्ट्रेन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश में मौजूद 73 वायरस रिसर्च लैब लगातार सैंपल की जांच कर रही हैं। इन लैब में आए सैंपलों में इन्फ्लुएंजा ए एच1एन1 पीडीएम-09 वायरस मिला है। यह वही वायरस है, जो 2025 से देश में फैल रहा है। इसकी जीन जांच में इसे क्लेड 6बी.1ए.5ए.2ए और सब-क्लेड डी.3.1.1 में रखा गया है। इसका मतलब है कि वायरस में जो बदलाव है, वह हर साल होने वाला सामान्य बदलाव है, जिसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। इस तरह के छोटे बदलाव हर साल होते हैं और इससे वायरस अधिक खतरनाक नहीं बनता। इसलिए जनता को डरने की जरूरत नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी और आईसीएमआर मिलकर देशभर में निगरानी कर रहे हैं। हर राज्य से रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है। अस्पतालों में दवा और जांच किट उपलब्ध हैं। सरकार का कहना है कि यदि कोई असामान्य बदलाव दिखेगा तो तुरंत कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

डॉक्टरों के अनुसार मौसमी इन्फ्लुएंजा से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को होता है। इन लोगों को भीड़भाड़ से बचना चाहिए और सर्दी-खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आम लोगों में इसके लक्षण सामान्य होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, बदन दर्द, गले में खराश और थकान। अधिकतर लोग पांच से सात दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन लापरवाही करने पर यह निमोनिया में भी बदल सकता है। बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। इसके लिए हाथों को बार-बार साबुन से धोएं, खांसते या छींकते समय रुमाल या कोहनी का इस्तेमाल करें, भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें। एंटीबायोटिक दवाएं इस वायरस पर काम नहीं करतीं।

सोशल मीडिया पर फ्लू को लेकर कई अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग इसे नई महामारी बता रहे हैं। सरकार ने कहा है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूत्रों की जानकारी पर भरोसा करें। केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार हैं और टेस्टिंग लैब 24 घंटे काम कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई बढ़ाने की भी योजना है।

मौसमी इन्फ्लुएंजा कोई नया खतरा नहीं है। यह हर साल बदलते मौसम में आता है और चला जाता है। वायरस में जो बदलाव है, वह सामान्य है। इसलिए डरने के बजाय सावधानी बरतें, साफ-सफाई रखें और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। घबराहट नहीं, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

फसल बीमा योजना से क्यों टूट रहा किसानों का भरोसा

73 लाख किसान चार साल में बाहर, 388 लाख हेक्टेयर का नुकसान

सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज अपने ही लक्ष्य से भटकती दिख रही है। पिछले चार साल में 73 लाख किसानों ने इस योजना को छोड़ा है और करीब 388 लाख हेक्टेयर रकबा बीमा से बाहर हो गया है। यह कोई सामान्य गिरावट नहीं है, यह किसानों के भरोसे की गिरावट है।

तालिका पर गौर करें तो 2023 में 240 लाख किसान बीमित थे। 2024 में यह संख्या 247 लाख हुई, लेकिन 2025 में गिरकर 201 लाख और 2026 में मात्र 174 लाख रह गई। प्रीमियम संग्रह 20,582 करोड़ से घटकर 349 करोड़ नहीं, बल्कि वास्तविक भुगतान और क्लेम का अंतर बहुत बड़ा है। किसानों को जितना मिलना चाहिए था, उसका आधा भी नहीं मिला।

किसानों के साथ बीमा कंपनियों का खेल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि बीमा कंपनियां प्रीमियम लेने में सबसे आगे हैं, लेकिन भुगतान के समय सबसे पीछे हो जाती हैं। गांव में सर्वे के नाम पर खानापूर्ति होती है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट देर से होते हैं और तकनीकी खामियों का हवाला देकर क्लेम रोक दिया जाता है।

कई राज्यों में बीमा कंपनियों ने मनमाने तरीके से आपत्तियां लगाई हैं। कहीं पोर्टल बंद होने का बहाना, तो कहीं दस्तावेज अधूरे होने का तर्क। किसान चक्कर लगाते-लगाते थक जाता है और योजना से ही बाहर हो जाता है। यह स्थिति तब है, जब केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में देती हैं। यानी कंपनी को घाटा नहीं, बल्कि मुनाफा ही मुनाफा है।

क्यों दूर हो रहा किसान? इसकी सबसे बड़ी वजह जटिल प्रक्रिया है। किसान को

बीमा कराने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार बैंक खुद ही प्रीमियम काट लेता है, लेकिन रसीद नहीं देता। जब नुकसान होता है तो पता चलता है कि बीमा ही नहीं हुआ।

दूसरी बड़ी समस्या भुगतान में देरी है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और सूखे के बाद किसान को तुरंत मदद चाहिए, लेकिन क्लेम छह महीने से साल भर बाद आता है। तब तक किसान साहूकार के कर्ज में डूब चुका होता है। तीसरी समस्या आंशिक भुगतान की है। कई बार पूरे गांव में फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन बीमा कंपनी केवल कुछ किसानों को ही भुगतान करती है और वह भी आधा-अधूरा। इससे भरोसा टूटता है।

सरकार को समझना होगा कि फसल बीमा कोई कॉरपोरेट योजना नहीं है। यह किसानों की जीवनरेखा है। यदि कंपनियां मनमानी करेंगी तो योजना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

सरकार को तीन कड़े कदम उठाने चाहिए। पहला, बीमा कंपनियों पर जुर्माने और ब्लैकलिस्ट की व्यवस्था हो। यदि तय समय में क्लेम नहीं दिया गया तो ब्याज सहित भुगतान और दंड लगे। दूसरा, सर्वे प्रक्रिया में किसान संगठनों और पंचायतों की भागीदारी हो, ताकि पारदर्शिता आए। तीसरा, भुगतान सीधे डीबीटी से और समयबद्ध हो।

73 लाख किसानों का योजना छोड़ना खतरे की घंटी है। यह बताता है कि किसान अब बीमा को सुरक्षा नहीं, बल्कि एक और बोझ समझने लगा है। यदि समय रहते कंपनियों की जवाबदेही तय नहीं हुई तो आने वाले समय में यह योजना केवल कागजों में रह जाएगी और अन्नदाता फिर से प्रकृति और कर्ज के भरोसे अकेला खड़ा होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)